

सामरिक परिदृश्य में भारत , मालदीव संबंध एवं चीनी संकट

अवनीश कुमार शुक्ला शोधकर्ता, राजनीति विज्ञान

डॉ. शुभा द्विवेदी असिस्टेंट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष

राजनीति विज्ञान विभाग, डी.एस.एन. कॉलेज उन्नाव

सारांश

यह शोध पत्र सामरिक परिदृश्य में भारत मालदीव संबंध एवं चीन की उसमें भूमिका को दर्शाता है। यह विश्लेषण वर्तमान में भारत एवं मालदीव के बीच के संबंध को भौगोलिक आर्थिक एवं राजनीतिक मानदंडों पर व्याख्यायित करने पर आधारित है।

इसके तहत यह बताने का प्रयास किया गया है कि कैसे चीन ने मालदीव की घरेलू राजनीति को राष्ट्रपति मुइज्जु के माध्यम से नियंत्रित करने का प्रयास किया है, और साथ ही साथ भारत एवं मालदीव के ऐतिहासिक संबंधों को कमजोर करने का प्रयास किया है। पर्यटन पर आधारित मालदीव की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान भारतीय पर्यटकों का रहा है परंतु मालदीव और भारत के बीच बढ़ते तनाव के कारण मालदीव के पर्यटन में गिरावट दर्ज की गई है, जिसके प्रतिउत्तर में चीनी समर्थक राष्ट्रपति मुइज्जु ने चीन को भारत के ऊपर तरजीह देने का प्रयास किया है।

इस शोध पत्र में चीन की महत्वपूर्ण वन बेल्ट वन रोड परियोजना का मालदीव के ऊपर प्रभाव तथा चीन की ऋण –जाल नीति के प्रभाव का मूल्यांकन किया गया है।

श्री मोदी द्वारा 6 जनवरी को अपने एक्स हैंडल पर भारत के पश्चिमी तट पर प्राचीन लक्षद्वीप द्वीप समूह की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करने के बाद मालदीव के तीन अधिकारियों द्वारा सोशल मीडिया पर भारत और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की गई, जिसके पश्चात भारतीय पर्यटकों ने द्वीपसमूह का बहिष्कार करने का आह्वान किया। कई मशहूर हस्तियों सहित करोड़ों भारतीयों ने अपना आरक्षण रद्द कर दिया और मालदीव जाने की योजना रद्द कर दी। पर्यटन आगमन के आँकड़े दर्शाते हैं कि शीर्ष पर्यटक देश होने से, भारत का स्थान जनवरी के बाद पहले पाँचवें और अब छठे स्थान पर आ गया है।

मालदीव के पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, इस साल 10 अप्रैल तक, कुल 6,63,269 पर्यटक आए, जिनमें से चीन 71,995 के साथ शीर्ष पर रहा, इसके बाद यूनाइटेड किंगडम (66,999), रूस (66,803), इटली (61,379) रहे। , जर्मनी (52,256) और भारत (37,417) रहे।

मुख्य शब्द:

इंडिया आउट

ऋण –जाल

वन बेल्ट वन रोड

मुइज्जू ने अपना पूरा राष्ट्रपति अभियान सोलिह के खिलाफ भारतीय सैन्य उपस्थिति की उपस्थिति पर बनाया था। 'इंडिया आउट' अभियान से प्रमुखता से उभरे चीन समर्थक नेता ने सोलिह पर द्वीप राष्ट्र में भारतीय सैनिकों को अनुमति देने का आरोप लगाया था।

राष्ट्रपति बनने के बाद मुइज्जू ने 77 भारतीय कर्मियों को हटाने की मांग की और भारत के साथ 100 समझौतों की समीक्षा का भी आदेश दिया। दोनों पक्ष भारतीय सैन्य प्लेटफार्मों का उपयोग जारी रखने के लिए 'व्यावहारिक समाधान' पर चर्चा करने पर सहमत हुए। हालाँकि उन्होंने कहा कि उनका इरादा भारत और चीन दोनों के साथ काम करने का है, लेकिन मुइज्जू का रुख भारतीय विदेश नीति के लिए एक बड़ा सिरदर्द बना हुआ है।

यह महत्वपूर्ण है कि भारत के भीतर माले के विरोध और अति राष्ट्रवादी आह्वान के बावजूद, नई दिल्ली ने मुइज्जू सरकार से संपर्क करना बंद नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर में श्री मुइज्जू से मुलाकात की और पेचीदा मुद्दों पर द्विपक्षीय बातचीत के लिए एक उच्च स्तरीय कोर ग्रुप का गठन किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी पिछले सप्ताह मालदीव के अपने समकक्ष से मुलाकात की थी। आशा है कि दोनों पक्षों को एहसास होगा कि उनके तनाव केवल उन समस्याओं के लक्षण हैं जो बड़ी हो सकती हैं: प्रथम, एक क्षेत्रीय शक्ति जो वैश्विक शक्ति बनने की आकांक्षा रखती है, और द्वितीय, एक द्वीपसमूह जो अपनी आर्थिक और क्षेत्रीय सुरक्षा जरूरतों के लिए बाहरी ताकतों पर निर्भर है। हालाँकि किसी भी देश के लिए संप्रभुता सर्वोपरि है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि दोनों पक्ष टकराव के बजाय शांति का लाभ देखें। भारत के लिए, जिसकी पड़ोस प्रथम नीति अपने पड़ोसी की प्राथमिकताओं के अनुसार मदद करने पर केंद्रित है, इसे मालदीव पर अपनी सेना थोपने के रूप में देखा जाना अनुचित है, जिसने मानवीय अभियान चलाए हैं। मुइज्जू सरकार के लिए, जो हाल ही में माले मेयर के लिए एक महत्वपूर्ण चुनाव हार गई है, आगामी मजलिस (संसदीय) चुनावों पर भारत के साथ दुश्मनी का प्रभाव भी चिंता का विषय होना चाहिए। व्यापक रूप से चीन समर्थक नेता के रूप में देखे जाने वाले मुइज्जू ने पिछले साल का राष्ट्रपति चुनाव 'भारत विरोधी' रुख के कारण जीता था, जब उन्होंने "इंडिया आउट" अभियान का नारा दिया था, उनकी सरकार की भारतीय कर्मियों को बाहर निकालने की योजना और तुर्किये, संयुक्त अरब अमीरात और चीन की यात्राओं को प्राथमिकता देने का उनका निर्णय, इसे और अधिक चिंताजनक बना दिया है।

मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में सबसे पहले नई दिल्ली का दौरा करने की परंपरा के विपरीत उन्होंने बीजिंग को अपना पहला बंदरगाह बनाया। इस बीच, मालदीव के राष्ट्रपति ने अपनी मौजूदा यात्रा में देश के पर्यटन उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण वकालत की, चीनी पर्यटकों से आग्रह किया कि वे आगमन के मामले में अपना शीर्ष स्थान पुनः प्राप्त करें, जो कि पिछले दो वर्षों से प्रभावी रूप से भारतीय पर्यटकों की स्थिति को प्रतिस्थापित कर दे।

चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना तथा ऋण -जाल कूटनीति

उनके भाषण के अनुसार, उन्होंने 2014 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा शुरू की गई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) परियोजनाओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने "मालदीव के इतिहास में देखी गई सबसे महत्वपूर्ण

बुनियादी ढांचा परियोजनाएं प्रदान कीं।" राष्ट्रपति शी के साथ अपनी बैठक में, मालदीव के नवनिर्वाचित नेता ने बीआरआई की सराहना की, और कहा कि उनका देश सहयोग के नए चैनलों का विस्तार करने और बेल्ट एंड रोड के निर्माण में उच्च गुणवत्ता वाली साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए तत्पर है।

संयुक्त बयान के अनुसार, चीन ने कहा कि वह मालदीव के "राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुकूल विकास पथ की खोज" का "सम्मान और समर्थन" करता है, और मालदीव के आंतरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप का "दृढ़ता से विरोध" करता है। यह संयुक्त बयान मालदीव की चीन के साथ बढ़ती नजदीकी तथा भारत से विरोध को दर्शाता है।

उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर पोस्ट किए गए एक विश्लेषण के अनुसार, "पहले चीन हमारा नंबर एक बाजार था, और मेरा अनुरोध है कि हम चीन को इस स्थिति को दोबारा से प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करें।" इस बीच, मालदीव मीडिया ने बताया कि चीन और मालदीव ने हिंद महासागर द्वीप पर एक पर्यटन क्षेत्र विकसित करने के लिए 50 मिलियन डालर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं, पीटीआई ने बताया कि मालदीव और चीन ने चीन समर्थक राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन प्रशासन के दौरान दिसंबर 2014 में एफटीए पर हस्ताक्षर किए थे। 2022 में चीन-मालदीव द्विपक्षीय व्यापार कुल मिलाकर 451.29 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें मालदीव से 60,000 अमेरिकी डॉलर के निर्यात के मुकाबले चीन का निर्यात 451.28 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। मालदीव राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने मालदीव इन्वेस्टमेंट फोरम में 11 परियोजनाओं को शुरू करने के लिए चीनी कंपनियों से निवेश भी मांगा। परियोजनाओं में माले वाणिज्यिक बंदरगाह को थिलाफुशी में स्थानांतरित करना, वेलाना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकास परियोजना, 15 और हवाई अड्डों का निर्माण और एसईजेड का विस्तार शामिल है।

भारत ,चीन और मालदीव की राजनीति में तुर्की का प्रवेश

मुइज्जू से पहले, मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपतियों के लिए अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत आने की प्रथा थी। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह ने 2018 में पदभार संभालने के बाद अपनी पहली राजकीय यात्रा पर भारत का दौरा किया। यहां तक कि खुले तौर पर भारत विरोधी राष्ट्रपति और मुइज्जू के करीबी सहयोगी अब्दुल्ला यामीन ने दिसंबर 2013 में अपनी पहली यात्रा के लिए भारत को चुना। दिसंबर 2008 में, मोहम्मद नशीद ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत आए।

मुइज्जू का अपनी पहली विदेश यात्रा पर भारत की बजाय तुर्की जाने का फैसला उनके भारत विरोधी रुख का एक और संकेत बन गया है। हालांकि, न तो भारत और न ही कनाडा को चुनकर, राष्ट्रपति ने संकेत दिया होगा कि उनकी विदेश नीति एशियाई विरोधियों में से किसी की ओर नहीं झुकेगी, बल्कि केवल मालदीव पर ध्यान केंद्रित करेगी।

हालांकि, पहली यात्रा के लिए गंतव्य के रूप में तुर्की का चयन भारत-मालदीव संबंधों के लिए अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि अंकारा और नई दिल्ली के बीच कई संवेदनशील भू-राजनीतिक मुद्दों पर विवाद हो चुका है। तुर्की भारत के प्राथमिक प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के करीब है और एर्दोगन ने कश्मीर मुद्दे पर इस्लामाबाद को समर्थन दिया है। एर्दोगन

ने कथित तौर पर सितंबर में जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे का विकल्प भी मांगा है।

तुर्की और मालदीव के बीच राजनयिक संबंध 1979 में स्थापित हुए थे। तुर्की और मालदीव दो मित्र राष्ट्र हैं जो कई अंतरराष्ट्रीय प्लेटफार्मों, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र और इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) पर घनिष्ठ सहयोग में हैं। हालाँकि, तुर्की की पसंद विवादास्पद लगती है, पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने अंकारा पर "इस क्षेत्र में भारतीय विरोधी इस्लामी राजनीति" करने का आरोप लगाया है। सिब्बल ने मुइज्जु पर अनावश्यक रूप से उकसाने का भी आरोप लगाया। तुर्की और भारत भू-राजनीतिक मुद्दों पर ध्रुवीकरण कर रहे हैं, तुर्की भारत के प्राथमिक प्रतिद्वंद्वी, पाकिस्तान के करीब है और कश्मीर मुद्दे पर उसका समर्थन कर रहा है।

मुइज्जु का इंडिया आउट अभियान

पिछले साल श्री मुइज्जु की चुनावी जीत से हुई थी, जब उन्होंने "इंडिया आउट" अभियान का नारा दिया था, उनकी सरकार की भारतीय कर्मियों को बाहर निकालने की योजना और तुर्किये, संयुक्त अरब अमीरात और चीन की यात्राओं को प्राथमिकता देने का उनका निर्णय था। इसे और अधिक चिंताजनक बना दिया। चुनावों में भारत विरोधी मंच पर सत्ता में आने के बाद, मालदीव की नई सरकार ने भारतीय सैन्य कर्मियों को देश छोड़ने के लिए कहने और अपने जल के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के लिए भारतीय नौसेना के साथ समझौते को समाप्त करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया है। मुइज्जु ने पिछले साल के अंत में अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर तुर्की की यात्रा करने का दिखावा किया था, अब वह चीन की राजकीय यात्रा पर हैं और उन्हें विश्वास है कि वह द्वीप गणराज्य में भारत की प्रमुखता को कम कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुइज्जु सरकार के तीन उपमंत्रियों द्वारा पोस्ट की गई अपमानजनक टिप्पणियों की पृष्ठभूमि में दोनों देशों के बीच विवाद के बीच भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी का अनुरोध आया है। नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार, मालदीव में 88 भारतीय सैन्यकर्मियों हैं।

चीन से लौटने के बाद शनिवार को प्रेस से बात करते हुए राष्ट्रपति मुइज्जु ने परोक्ष रूप से भारत पर हमला बोला। उन्होंने किसी देश का नाम लिए बिना कहा, "हम छोटे हो सकते हैं, लेकिन इससे आपको हमें धमकाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता।" उन्होंने भारत पर देश की निर्भरता को कम करने की योजनाओं की भी घोषणा की, जिसमें अन्य देशों से आवश्यक खाद्य वस्तुओं और दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों के आयात को सुरक्षित करना शामिल है। उन्होंने अपने मीडिया बयान में आगे कहा कि हिंद महासागर "किसी विशेष देश का नहीं है", और मालदीव "किसी का पिछलग्गू नहीं है"।

श्री मुइज्जु की टिप्पणी, जाहिरा तौर पर भारत की ओर इशारा करते हुए, माले और नई दिल्ली के बीच बढ़ते तनाव के बीच आई है। सितंबर में श्री मुइज्जु के चुनाव के बाद से मालदीव-भारत द्विपक्षीय संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं, क्योंकि उनकी मांग है कि मालदीव से भारतीय सैनिकों को तेजी से वापस बुलाया जाए।

संदर्भ सूची (Reference)-

- i. Srinivasan, Meera, “ Maldives, China agree to elevate strateic cooperation. ” The hindu, January 14 ,(2024)
<https://www.thehindu.com/news/international/maldives-china-agree-to-elevate-strategic-cooperation/article67730447.ece>
- ii. EU report (2023).“Maldives ruling coalition deployed anti-India sentiments during 2023 presidential polls” <https://www.thehindu.com/news/national/maldives-ruling-coalition-deployed-anti-india-sentiments-during-2023-presidential-polls-eu-report/article67726586.ece>
- iii. Singh, Abhijit, “ An ‘India Out’ plan that could impact the Maldives ” The hindu, January 03 ,(2024) <https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/an-india-out-plan-that-could-impact-the-maldives/article67699297.ece>
- iv. Mulay, Dayaneshwar, “ India and Maldives ties: Despite China, bound by history and geography. ” The indian express, October 14 ,(2023)
<https://indianexpress.com/article/opinion/columns/india-and-maldives-ties-despite-china-bound-by-history-and-geography-8981993/>
- v. Haidar, Suhasini, “ Choppy waters: On India-Maldives ties ”, the hindu, January 25 (2024). <https://www.thehindu.com/opinion/editorial/choppy-waters-on-india-maldives-ties/article67773018.ece>
- vi. Karuna, V, (2018) “ Chinese research ship moors near Maldives after spending a month in Indian Ocean. ”, hindu, february 22 (2024).
<https://www.thehindu.com/news/international/chinese-research-ship-moors-near-maldives-after-spending-a-month-in-indian-ocean/article67874951.ece>

- vii. Mulay, Dayaneshwar “Maldives President Mohamed Muizzu seeks debt relief from India amid tensions. ”, hindu, march 23 (2024).
<https://www.thehindu.com/news/international/maldives-president-mohamed-muizzu-seeks-debt-relief-from-india-amid-tensions/article67983265.ece>
- viii. Srinivasan, Meera, “Maldives to hold road shows in India to woo tourists back. ”,the hindu, april 12 (2024).
- ix. <https://www.thehindu.com/news/international/maldives-to-hold-road-shows-in-india-to-woo-tourists-back/article68056954.ece>
- x. पंत, वर्धन, हर्ष (2012) “ भारतीय सुरक्षा एवं विदेश नीति ” ,प्रभात प्रकाशन ,नई दिल्ली पंत , पुष्पेश (2019), “ 21 वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध ”, टाटा मैकग्रा हिल्स,चेन्नई पृ0 सं0 IV.21, IV22.
- xi. सीकरी , राजीव ,(2009) “ भारत की विदेश नीति : चुनौती और रणनीति ”,सेज पब्लिकेशन ,नई दिल्ली पृ0 सं0 67-67,,



Contributors Details:

- 1.अवनीश कुमार शुक्ला (शोधकर्ता, राजनीति विज्ञान विभाग डी.एस.एन. कॉलेज उन्नाव)
- 2.डॉ. शुभा द्विवेदी (असिस्टेंट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान विभाग डी.एस.एन. कॉलेज उन्नाव)